forthe first was now as one at fider from which

the state of the second st

Product and with a second of the state of

आर. मीनाक्षी सुन्दरम्, सचिव.

उत्तराखण्ड शासन्।

सेवः में

निदेशक.

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुमाग-02

देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 आयोजनागत अन्तर्गत 01-डेरी विकास योजना (टी0एस0पी0) में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

STEEL VISION INC.

महोदय.

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1839-40/नियोजन-प्रस्ताव डे0वि0यो0/2017-18, दिनांक 12 फरवरी, 2018 के संदर्भ में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि चालू दित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

प्लांट मशीनरी एवंदर्य परिवहन एवं विपणन संसाधन हेत :-

<b>Φ</b> 0 <b>∀</b> i0	नाम जनपद	संसाधन जिसकी आवश्यकता है।	संख्या	प्रस्तावित धनराशि	विवरण
1.	खटीमा, ऊधमसिंहनगर	डीं०पीं०एम०सी०यू०	Q5	5.00	दुग्ध सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण हेतु टी०एस० पी0 समितियों में स्थापित किये जायेंगे।
	योग :			5.00	

- 1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फाँट निदेशक, डेरी विकास द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा
- 2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय ।
- 3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक / मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
- 4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उसी मद (उक्तांकित तालिका में उल्लिखित) पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
- 6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम0-08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेंगी।

7. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना

सुनिश्चित करेंगे।

8. किंसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय निमय संग्रह खण्ड-05 भाग-01 (लेखा नियम), आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूबना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।

धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर

ली जाए।

10. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन एवं समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ट उपलब्ध करायी जाय।

11. विमिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी

एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लेम्बित नहीं रखा जायेगा।

12. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि अनुसूचित जनजाति के सदस्य संख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत ही हो।

2— उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में अनुदान संख्या—31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2404—डेरी विकास—00—आयोजनागत—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—01—डेरी विकास योजना—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून 2017 के

कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम) सचिव।

संख्या- 146 (1)/XV-2/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- मण्डलायुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
- 4. दित्त अनुभाग-4, / नियोजन विभाग / समाज कल्याण नियोजन प्रकोच्छ, उत्तराखण्ड शासन।

5 निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, सम्पर्क / संयुक्त निदेशक, कार्यालय, देहरादून।

निदेशक, बजट राजकोषीय-नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परितर, देहरादून।

8. गार्ड पत्रावली।